



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 336]
No. 336]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 1986/श्रावण 29, 1908
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 1986/SRAVANA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जन्म भूतल परिवहन विभाग)

(सड़क पक्ष)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1986

अधिसूचना

का.भा 496 (अ)—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग (मणोघन) नियम 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग नियम, 1957 (जिन इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, "कार्यकारी अभिकरण" शब्दों के स्थान पर, जहाँ जहाँ वे आते हैं "कार्यान्वयन अभिकरण" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 2 में:—

(1) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

(ख) "अनुमोदित निर्माण कार्य" से कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है जो किसी ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, अनु-रक्षण और परम्पत के संबंधित या संसक्त है जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार ने नियम 3 के अधीन तकनीकी और प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान की है।"

(घ) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा:

(घ) "कार्यान्वयन अभिकरण" के निम्नलिखित अभिप्रेत हैं:—

(i) संघ क्षेत्र के मामले में, उसका प्रशासक जिसे संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित निर्माणकार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कृत्य प्रत्यायोजित किए जाते हैं, और

(ii) किसी अन्य मामले में, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का, जिसे अधिनियम की धारा 5 के अधीन ऐसे कृत्य प्रत्यायोजित किए जाते हैं, अधीनस्थ कोई अधिकारी या प्राधिकारी,

(iii) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:

(क) "सूची" से ऐभा अभिलेख अभिप्रेत है जो नियम 7 के उपनियम (2) के अधीन तैयार किए जाने, रखे जाने और दिए जाने के लिए अपेक्षित है,

(ख) "प्रगति रिपोर्ट" से नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित रिपोर्ट अभिप्रेत है,

(घ) "प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन निर्माण कार्य" से नियम 3 के उपनियम (2) निविष्ट कोई भी निर्माण कार्य अभिप्रेत है,

4. उक्त नियमों के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

3. निर्माणकार्य का प्राक्कलन उसका प्रारंभ, समाप्ति आदि

- (1) जहां किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी मूल निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए लागत का प्राक्कलन 25 लाख रुपए से अधिक है, वहां कार्यान्वयन अभिकरण निर्माणकार्य के निष्पादन की लागत का विस्तृत प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्रारूप में भेजेगा जैसा केन्द्रीय सरकार उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और वह सरकार ऐसे प्राक्कलन के तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए प्रदान कर सकेगी जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे।
- (2) जहां किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी मूल निर्माणकार्य के निष्पादन के लिए लागत का प्राक्कलन 25 लाख रुपए से अधिक न हो, वहां ऐसे निर्माणकार्य के निष्पादन के लिए ऐसे प्राक्कलन के तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी से संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रखते हुए प्रदान की जा सकेगी।
- (3) कार्यान्वयन अभिकरण, उपनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट निर्माणकार्य के संबंध में ऐसी विस्तृत सबखण और अन्वेषण करेगा, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट और उस आचार्य के प्रमाणपत्र के साथ सभी प्रस्ताव होने।
- (4) भूमि-अर्जन से संबंधित प्राक्कलन कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा तैयार की जाएगी और उसे कार्य घटक के लिए प्राक्कलनों की मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार के पास काफी समय पहले प्रस्तुत किया जाएगा।
- (5) उप-नियम (1) में निविष्ट निर्माणकार्य के लिए प्रस्ताव प्रक्रमों में केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित क्रम में भेजे जाएंगे :—
 - (क) इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्ताव उपर्दिष्ट करते हुए एक तकनीकी प्रकन टिप्पण ;
 - (ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत तकनीकी प्राचल (पैरामीटर) के आधार पर एक परियोजना प्राक्कलन।
- (6) (क) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (5) के खंड (क) से (ख) तक निविष्ट दस्तावेज प्राप्त हो जाने पर उनकी जाच करेगी और यदि उसकी यह राय है कि वे अनुमोदित मानक के अनुसार हैं, तो वह ऐसे निर्माण कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी

ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए मंजूरी प्रदान करेगी जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे।

(ख) यदि यह निर्माण कार्य उस अवधि में नहीं शुरू किया जाता है, तो खंड (क) के अधीन प्रदान किया गया तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी इसके जारी होने की तारीख से दो वर्षों के पश्चात् व्यपगत हो जाएगी।

परन्तु जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि तकनीकी प्रकन टिप्पण या परियोजना प्राक्कलन अनुमोदित मानक के अनुसार नहीं है, तो वह उसे कार्यान्वयन अभिकरण को अनुमोदित मानक के अनुसार करने के लिए लौटा देगी।

(7) उपनियम (2) में निविष्ट निर्माण कार्य के लिए विस्तृत प्राक्कलन कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा तैयार किया जाएगा। और ऐसी विस्तृत जानकारी जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, के साथ लागत की केवल सामान्य संक्षिप्त उस सरकार को नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रखते हुए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए भेजी जाएगी।

(8) ऐसे आपादिक मामलों को छोड़कर जहां उपनियम (1) और (2) में निविष्ट किसी निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए भूमि का अर्जन आवश्यक है, जहां ऐसे निर्माण कार्य की मंजूरी यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा या कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि, ऐसा अर्जन नहीं किया गया है, या ऐसे भूखंड का अर्जन किया गया है, जो यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या कार्यान्वयन अभिकरण की राय में ऐसे भूखंड पर निर्माण कार्य, पूरा होने के बावजूद यातायात को सुकर नहीं बनाएगा।

(9) किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई भी पुल निर्माण कार्य कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा तब तक प्रारंभ नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके संबंध में तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी समुचित, मंजूरी प्राधिकारी द्वारा प्रदान नहीं की गई हो।

परन्तु बाढ़, भूकम्प या कोई अन्य अनिवार्य बाध्यता जैसे आपात से उत्पन्न निर्माण कार्य के ऐसे मामलों में, जिन में कार्य प्रारंभ करना स्थगित नहीं किया जा सकता, उन्हें तत्काल प्रारंभ किया जा सकेगा किन्तु कार्यान्वयन अभिकरण उस आपात की प्रकृति और प्रस्तावित अनुमानित व्यय की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को तुरन्त भेजेगा।

(10) उप नियम (5) के खंड (ख) में निविष्ट परियोजना प्राक्कलन में निम्नलिखित रीति से परियोजना के निष्पादन के लिए कलेंडर मासों में समय-सूची और उससे संबंधित सभी क्रियाकलाप होंगे :

(क) सन्निर्माण पूर्ण प्रक्रम :—निविदा आमंत्रित करते हुए नोटिस जारी करना ; निविदा की प्राप्ति, और प्राक्कलन की मंजूरी की तारीख से निविदा को अन्तिम रूप देना।

(ख) सन्निर्माण प्रक्रम : कार्य सौंपने की तारीख से निर्माण कार्य के भाग रूप विभिन्न क्रियाकलापों के पूरा होने की अवधि।

(11) (क) कार्य निष्पादन के लिए निविदाएं उन अधिकारियों द्वारा आमंत्रित की जाएंगी जिन्हें यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा निविदाओं को स्वीकार करने के लिए सशक्त किया गया है।

(ख) निर्माण कार्य के लिए निविदा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रारूप में दी जाएगी।

(ग) आपवादिक मामलों को छोड़कर कार्यान्वयन अभिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से वह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना प्राक्कलन में सभी घटकों का निर्माण कार्य एक ही ठेकेदार को दिया जाता है और परियोजना प्राक्कलन में घटक अलग-अलग रूप में नहीं है।

(12) ठेकेदारों का वर्गीकरण :

(क) कार्यान्वयन अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदारों का विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अर्हित इंजीनियरों का नियोजन, उनके पास उपलब्ध मशीनरी की किस्म और विशेषज्ञता और नियत समय में उनके द्वारा कुछ कार्यभार करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण किया जाता है।

(ख) जटिल प्रकार के या निर्दिष्ट रकम से अधिक लागत वाले कार्य के लिए ठेकेदारों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट पूर्व अर्हता के अनुसार विचार किया जाएगा।

(13) क्वालिटी नियंत्रण :

कार्यान्वयन अभिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों पर क्वालिटी नियंत्रण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का और यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, या कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा मंजूर किए गए निर्माण कार्य के प्राक्कलनों में किए गए क्वालिटी नियंत्रण के उपबंध के उपयोग की पद्धति का भी अनुसरण करेगा।

(14) (क) जहां-जहां केन्द्रीय सरकार ने मशीनरी का प्रदाय किया है, उसका उपयोग उसी कार्य के निष्पादन के लिए किया जाएगा जिसके लिए उसका प्रदाय किया गया था।

(ख) कार्यान्वयन अभिकरण अभिलेखी इतिगत पत्रकों, संयंत्र झकड़ा पत्रकों और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदाय की गई मशीनरी के लिए लॉग बुकों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट भाड़ा प्रभार लेखा, अनुसंधान और मरम्मत पर खर्च का लेखा रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

(ग) कार्यान्वयन अभिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग की संहिता के अनुसार दी गई मशीनरी का लेखा भी रखेगा।

(घ) खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदाय की गई मशीनरी और अभिलेख, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा सब उपयुक्त समय पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 4 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(1) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी खंड के अनुसंधान के लिए विस्तृत प्राक्कलन

की विशिष्टियों की संक्षिप्त कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्रारूप में जो केन्द्रीय सरकार, अपेक्षा करे, 1 मई तक या उस वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे दिन तक जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, भेजेगा।

(1) क. कार्यान्वयन अभिकरण विशिष्टियों की उक्त संक्षिप्ति में वार्षिक नवीकरण कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित केन्द्रीय सरकार के प्रादेशिक अधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी खंड के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप में बार-चाटों द्वारा समर्थित हो, सम्मिलित करेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी विशिष्ट मामले में या मामलों के किसी वर्ग से कार्यान्वयन अभिकरण से किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुसंधान के लिए विस्तृत प्राक्कलन ऐसे प्रारूप में जो वह सरकार अपेक्षा करे, भेजने की अपेक्षा कर सकेगी।”

6. उक्त नियमों के नियम 5 में :—

“10 लाख रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं “पच्चीस लाख रु.” शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“7 प्रगति रिपोर्ट और सूची :

(1) कार्यान्वयन अभिकरण, ऐसे राजमार्ग पर मंजूर किए गए निर्माण कार्य की प्रगति मानिटर करने के प्रयोजन के लिए ऐसे राजमार्ग के निर्माण कार्य से संबंधित मुख्य इंजीनियर के कार्यालय से मानिटर कक्ष स्थापित करेगा और कार्यान्वयन अभिकरण ऐसे निर्माण कार्यों के संबंध में कार्यान्वयन प्रगति रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्रारूप में और ऐसे अंतरालों पर देगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(2) (क) कार्यान्वयन अभिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप से राष्ट्रीय राजमार्गों और खराब सड़कों के माप की सूची तैयार करेगा और रखेगा जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।

(ख) खंड (क) के अधीन तैयार की गई और अद्यतन बनाई गई सूची केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अंतरालों पर उसे दी जाएगी।”

8. उक्त नियमों के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“8. निर्माण कार्य में विवर्जन, घटिया निर्माण कार्य और समाप्ति रिपोर्ट :

(1) कार्यान्वयन अभिकरण समुचित मंजूरी प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना; परियोजना के विनिर्देशों और डिजाइन की परिधि में से विचलन नहीं करेगा। ऐसा होने पर विचलन किए गए निर्माण कार्य के घटक और उससे प्रभावित निर्माण कार्य के अन्य घटकों पर हुए व्यय को कार्यान्वयन अभिकरण के प्रति विकलित किया जाएगा।

(2) घटिया निर्माण कार्य, यदि कोई हो का उत्तरदायित्व कार्यान्वयन अभिकरण पर होगा और ऐसे घटिया निर्माण कार्य से उत्पन्न सभी व्ययों को कार्यान्वयन अभिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने खर्च पर दूर करेगा।

(3) (क) कार्यान्वयन अभिकरण पूरा किए गए कार्य के रेखा-चित्र के साथ समाप्ति रिपोर्ट कार्य समाप्त होने की वास्तविक तारीख या राजमार्ग को यातायात के लिए खोले जाने के छह मास के भीतर इन दोनों में से जो भी पहले हो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूपों में भेजेगा।

(ख) रिपोर्ट के साथ इस अध्याय का प्रमाणपत्र भी होगा कि परियोजना विहित परिधि, विनिर्देशों और अनुमोदित डिजाइनों के अनुसार पूरी की गई हैं।

(ग) यथाशक्य शीघ्र और खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट रिपोर्ट और प्रमाणपत्र देने के पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण अन्य बातों के साथ-साथ व्यय के आकड़े देते हुए वित्तीय रिपोर्ट देगा।

9. उक्त नियमों के नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम किया जाएगा अर्थात् :—

“9. निर्माण कार्य का निरीक्षण :

भारत सरकार को महानिदेशक (सड़क विकास) या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी भी समय चल रहे या पूर्ण हो गए अनुमोदित निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक निरीक्षण की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।”

10. उक्त नियमों की अनुसूची में :—

(क) शीर्ष में, “(नियम 3(2) देखें)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “(नियम 3(2) और 3(7) देखें)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ख) शर्त (1) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) कार्यान्वयन अभिकरण, किसी विशिष्ट वर्ग के लिए निर्माण कार्यों के वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए अंतिम ब्यौरे में अंतर्विष्ट विशिष्टियों की बाबत विस्तृत जानकारी के साथ लागत के सामान्य संक्षिप्त अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। कार्यान्वयन अभिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने की तारीख से तीन मास के भीतर पहले ही तैयार किए गए विस्तृत प्राक्कलन को तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान करेगा और तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान करने की तारीख से छह मास के भीतर कार्य शुरू कर देगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया गया प्रशासनिक अनुमोदन स्वतः खूब हो जाएगा और कार्यान्वयन अभिकरण उक्त कार्य के लिए नए सिरे से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करेगा।”

(ग) शर्त (4) और शर्त (9) में “10 लाख रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “पच्चीस लाख रु.” शब्द रखे जाएंगे।

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 13-4-1957 में परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) की सरकारी अधिसूचना सं. का.नि.प्रा. 1181 तारीख 4-4-1957 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनका संशोधन निम्नलिखित द्वारा किया गया था :—

(1) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. का.प्रा. 680(अ) तारीख 15-10-76।

[फा. सं. धार. डब्ल्यू/एन. एन. III/वी/1/85]

कुण कुमार सीन, महानिदेशक (सड़क विकास)
और अपर सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

(Roads Wing)

New Delhi, the 20th August, 1986

NOTIFICATION

S.O. 496 (E) :—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Rules, 1957, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Highways (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Rules, 1957 (hereinafter referred to as the said rules), for the words “executive agency”, wherever they occur, the words “executing agency” shall be substituted.

3. In rule 2 of the said rules, —

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

(b) “approved work” means any work relating to, or connected with, the development, maintenance, and repair of a national highway in respect of which the Central Government has accorded technical and administrative approval and financial sanction under rule 3;

(ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

(d) “executing agency” means,

(i) in the case of a union territory, the administrator thereof to whom the functions of the Central Government in relation to the execution of works pertaining to national highways are delegated under article 239 of the Constitution; and

(ii) in any other case, any officer or authority subordinate to the Central Government or the State Government to which such functions are delegated under section 5 of the Act;

(iii) for clause (e), the following clauses shall be substituted, namely :—

(e) “inventory” means a record as required to be prepared, maintained and furnished under sub-rule (2) of rule 7;

- (f) "progress report" means a report required to be furnished under sub-rule (1) of rule 7;
- (g) "work under delegated powers" means any work referred to in the sub rule (2) of rule 3;
4. For rule 3 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—
3. Estimate of work, its commencement, completion, etc.
- (1) where the estimates of the cost for the execution of any original work on a national highway exceeds Rs. 25 lakhs, a detailed estimate of the cost for the execution of the work shall be forwarded by the executing agency to the Central Government in such form as the Central Government may specify in that behalf and that Government may accord technical approval and financial sanction to such estimate subject to such conditions as it may think fit to impose.
- (2) Where the estimate of the cost for the execution of any original work on a national highway does not exceed Rs. 25 lakhs, technical approval and financial sanction to such estimate for the execution of such work may be accorded by the executing agency concerned subject to the conditions specified in the Schedule annexed to these rules.
- (3) The executing agency shall undertake detailed survey and investigations with regard to the work specified in sub rules (1) and (2), as the Central Government may specify and a certificate to that effect shall accompany all proposals.
- (4) The estimates relating to the acquisition of land, shall be prepared by the executing agency and submitted for sanction to the Central Government well in advance of the estimates for the work component.
- (5) For the work referred to in sub-rule (1), the proposals shall be sent to the Central Government in stages in the following order :—
- (a) a technical appraisal note indicating the proposal in the form specified by the Central Government in this behalf;
- (b) a project estimate on the basis of the technical parameters laid down by the Central Government in this regard.
- (6) (a) The Central Government shall, on receipt of the documents referred to in clauses (a) to (b) of sub rule (5), examine the same and if it is of the opinion that they are in accordance with approved standard, shall accord technical approval and financial sanction for such work subject to such conditions as it may think fit to impose.
- (b) The technical approval and financial sanction accorded under clause (a) shall lapse after two years from the date of its issue in case the work is not commenced within that period.
- Provided that where the Central Government is of the opinion that the technical appraisal note or project estimate is not in accordance with the approved standard, it may return the same to the executing agency for bringing it in accordance with the approved standard.
- (7) For the work referred to in sub rule (2), a detailed estimate shall be prepared by the executing agency and only the general abstract of cost alongwith detailed information as the Central Government may specify, shall be forwarded to that Government for accord of administrative approval subject to the conditions specified in the Schedule annexed to the rules.
- (8) Save in exceptional cases, where acquisition of land is necessary for the execution of any work referred to in sub rule (1) and (2), sanction to such work shall not be accorded by the Central Government or, as the case may be, by the executing agency, unless such acquisition has been given effect to, or on acquisition of such section of land which in the opinion of the Central Government or the executing agency as the case may be would facilitate traffic even if work is completed on such section of land.
- (9) No original work on any national highway shall be commenced by the executing agency until technical approval and financial sanction thereon have been accorded by the appropriate sanctioning authority.
- Provided that in cases of work arising out of emergency, such as flood, earthquake or any other force majeure, the commencement of which cannot be postponed, may be commenced immediately but the executing agency shall immediately report to the Central Government the nature of the emergency and the approximate expenditure involved.
- (10) The project estimate referred to in clause (b) of sub rule (5) shall contain a time schedule in calendar months for execution of the project in the following manner and all the activities shall be related thereto :
- (a) Pre-construction stage
Issue of notice inviting tender ;
receipt of tender ; and
finalisation of tender from the date of sanction of estimate.
- (b) Construction stage.
Period of completion of various activities forming part of the work from the date of award of work.
- (11) (a) The tenders for the execution of work shall be invited by the Officers empowered by the Central Government or the executing agency, as the case may be, to accept them.

- (b) The work shall be tendered in the form specified by the Central Government in this regard.
- (c) Save as exceptional cases with the prior approval of the Central Government, the executing agency shall ensure that the work of all components in the project estimate is awarded to a single contractor and that the components in the project estimate are not split horizontally.

(12) Classification of contractors.

- (a) The executing agency shall ensure that contractors are classified for jobs of various sizes, taking into consideration, employment of qualified engineers, kind of machinery and expertise available with them and the total workload which they can handle at a given time;
- (b) The contractors for works of intricate nature or costing more than a specified amount as specified from time to time by the Central Government shall be considered for prequalification.

(13) Quality control.

The executing agency shall follow the directions issued by the Central Government from time to time for exercising quality control of national highway works as also the modes of utilising the quality control provisions made in the estimates of work sanctioned by the Central Government or the executing agency as the case may be.

- (14) (a) The machinery wherever supplied by the Central Government shall be used in the execution of the work for which it was supplied.
- (b) The executing agency shall be responsible for maintenance of records, history sheets, plant data sheets and log books for the machinery supplied by the Central Government as well as hire charge account, expenditure account on maintenance and repairs, as specified from time to time by the Central Government.
- (c) The executing agency shall maintain accounts of the machinery provided by the Central Government as per PWD Code.
- (d) The machinery supplied by the Central Government and the records referred to in clause (b) and (c) shall be made available for inspection by the officers of the State Government and the Central Government at all reasonable times.

5. In rule 4 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

- “(1) An abstract of the particulars of the detailed estimate for maintenance of each National Highway or a section thereof requiring maintenance during a financial year shall be forwarded by the executing agency to the Central Government in such form as the Central Government may require, not

later than the 1st day of May or such other day as may be specified by the Central Government in that financial year.

- (1) A The executing agency shall in the said abstract of particulars include an annual renewal programme supported by bar charts in the form specified for each national highway or a section thereof approved by the regional officer of the Central Government dealing with national highways :

Provided that the Central Government may in any particular case or class of cases, require the executing agency to forward a detailed estimate for the maintenance of any national highway in such form as that Government may require.”

- 6. In rule 5 of the said rules —
for the words and figures ‘Rs. 10 lakhs’, wherever they occur, the words “twenty five lakhs” shall be substituted.

7. For rule 7 of the said rules the following rule shall be substituted, namely :—

“7 Progress reports and inventory :—

- (1) The executing agency shall establish monitoring cells for the purpose of monitoring the progress of sanctioned work on a national highway, in the office of the Chief Engineer concerned with the works of such highway and the executing agency shall furnish to the Central Government progress reports in respect of such works in such form and at such intervals as may be specified by the Central Government from time to time.
- (2) (a) The executing agency shall prepare and maintain inventory of national highways and measurement of roughness of the roads in the form specified by the Central Government, which shall be updated periodically.
- (b) The inventory prepared and updated under clause (a) shall be furnished to the Central Government at such intervals as may be specified by it.”

8. For rule 8 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

“8. Deviation in work, sub-standard work and completion report :—

- (1) The executing agency shall not without the prior sanction of the appropriate sanctioning authority, deviate from the scope of the specifications and design of the project, failing which the expenditure on the component of the deviated work and the other components of the works affected thereby shall be debited to the executing agency.
- (2) The responsibility for the sub-standard work, if any, shall rest with the executing agency and all defects arising out of such sub-standard work shall be rectified by the

executing agency at its own cost, within the period to be specified by the Central Government.

- (3) (a) The executing agency shall furnish to the Central Government a completion report along with the drawings of the completed work in such forms as the Central Government may specify within six months of the actual date of completion, or from opening to traffic whichever is earlier.
- (b) The report shall also be accompanied by a certificate to the effect that the project has been completed according to the prescribed scope, specifications and approved designs.
- (c) As early as possible and after furnishing of the report and certificate specified in clauses (a) and (b) the executing agency shall furnish a financial report giving, inter alia, the expenditure figures.

9. For rule 9 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

“9 Inspection of work

Director General (Road Development) to the Government of India or any officer authorised by him in this behalf may inspect at any time any approved work in progress or completed work and a report of every such inspection shall be submitted to the Central Government.”

10. In Schedule to the said rules

- (a) in the heading, for the words, brackets and figures “[See rule 3 (2)] the words brackets and figures” [See rules 3 (2) and 3(7)] shall be substituted;

- (b) for condition (1), the following condition shall be substituted, namely :—

“(i) The executing agency shall forward to the Central Government for approval general abstract of cost along with detailed information in respect of the particulars contained in the tentative details given in the annual programme of works for a particular year. The executing agency shall accord technical approval and financial sanction to the detailed estimate already prepared within three months from the date of according administrative approval by the Central Government; and shall commence execution of the work within six months from the date of according technical approval and financial sanction failing which, the administrative approval accorded by the Central Government shall stand cancelled automatically and the executing agency shall approach the Central Government for fresh administrative approval for the said work.”

- (c) in conditions (4) and (9) for the words and figure “Rs. 10 lakhs”, the words “rupees twenty five lakhs” shall be substituted.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3 sub Section (ii) dated 13-4-57 vide Government Notification, Ministry of Transport (Roads Wing) No. S.R.O. 1181 dated 4-4-57 and was subsequently amended by :—

- (i) Government notification No. SO-680 (E) dated 15-10-76 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub Section (II).

[F. No. RW/NHIII/P/1/85]

K. K. SARIN, Director General (Road Development)
and Addl. Secy.

